

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1041/2021

राजेन्द्र शेखर भक्कड़

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.02.2021

आदेश की दिनांक : 05.06.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष तोमर, कैवियटर

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 1.11.2012 के आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी की 2012-13 की रिक्ति के विरुद्ध आरएएस सुपर टाइम स्केल के पद पर पदोन्नति के लिए परिणाम खोलें तथा परिणाम खोलने के पश्चात अपीलार्थी को 2012-13 की रिक्ति के विरुद्ध आरएएस, सुपर टाइम स्केल के पद पर सभी परिणामी लाभों सहित पदोन्नति की अनुमति दी जावे। साथ ही अपीलार्थी के मामले पर विचार करें तथा उसे आरएएस, उच्च सुपरटाइम स्केल के पद पर उस तारीख से पदोन्नति दें, जिस तारीख को उसके कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था, जो वर्ष 2017 से संबंधित है तथा सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नति आदेश जारी किया जावे।

अपीलार्थी दिनांक 1.11.2012 के उस आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी का आरएएस सुपर टाइम स्केल के पद पर पदोन्नति का परिणाम आपराधिक मामले के लंबित रहने के आधार पर सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। आरएएस हायर सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी के दिनांक 5.10.2020 के अभ्यावेदन पर भी निर्णय नहीं लिया गया। (अनुलग्नक-1 व 2) अपीलार्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग के आदेश दिनांक 24.2.1989 के अनुसार फरवरी 1989 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जूनियर स्केल में प्रारंभिक रूप से शामिल किया गया था। (अनुलग्नक-3) अपीलार्थी को वर्ष 1995 में आरएएस, वरिष्ठ स्केल के पद पर पदोन्नत किया गया था और आगे उसे वर्ष 2007 में आरएएस चयन स्केल के संवर्ग में पदोन्नति प्रदान की गई थी। दिनांक 1.4.2011 को आरएएस चयन स्केल के संवर्ग में वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें चयन वर्ष 2005-06 के पदोन्नत व्यक्ति के रूप में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 95 पर रखा गया था। (अनुलग्नक-4) इसी प्रकार आरएएस सीनियर स्केल संवर्ग में दिनांक 1.4.2012 को अगली वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 87 पर दर्शाया गया था। (अनुलग्नक-5) उसे वर्ष 2012-13 के लिए आरएएस सुपर टाइम स्केल के संवर्ग में उसकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिलनी थी तथा अपीलार्थी के मामले पर विचार किया गया था, लेकिन अपीलार्थी के परिणाम को दिनांक 1.11.2012 के आदेश द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। (अनुलग्नक-1) अपीलार्थी विरुद्ध वर्ष 2007 में पंजीकृत आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसका पदोन्नति परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। इस संबंध में अपीलार्थी ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि एडीएम सिटी, गंगानगर के रूप में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में काम करते हुए अपीलार्थी ने एम.एल. गन के पहले से जारी लाइसेंसों पर बी.एल. गन की कुछ अनुमति जारी की। अपीलार्थी ने लाइसेंस जारी नहीं किए थे, बल्कि कुछ लोगों को अतिरिक्त अनुमति दी थी, लेकिन कुछ शिकायतों के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ एसीबी में मामले दर्ज किए गए थे। अतिरिक्त अनुमति जारी करने से संबंधित एक ही मुद्दे के संबंध में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गईं और दो मामले लाइसेंस के नवीकरण के अनुदान से संबंधित हैं, जिन्हें पंजाब में रद्द कर दिया गया था। इसलिए, अपीलार्थी ने एक अधिकारी के रूप में काम किया और उसने एसीबी अधिनियम या शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध नहीं किया है,

लेकिन झूठी शिकायत के आधार पर, मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गईं, जिससे एक ही मुद्दा अलग-अलग कोनों से अलग हो गया। (अनुलग्नक-6) जहां तक आपराधिक मामले का संबंध है, आपराधिक मामलों में, 5 एफआईआर के विरुद्ध, एक मामले में अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई थी और अन्य चार मामलों में वर्ष 2012 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के बाद चालान दायर किया गया है। जहां तक आरोप तय करने का सवाल है, वे वर्ष 2017 में तय किए गए थे और आरोप तय करने वाले प्राधिकारी के खिलाफ अपीलार्थी ने मुख्य सीट जोधपुर में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक याचिका दायर की थी और उक्त याचिका अभी भी अंतिम निर्णय के लिए लंबित है और उसी सादृश्य के आधार पर आरएएस के उच्च सुपर टाइम स्केल के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति के मामले पर विचार नहीं किया गया था और उसे खारिज कर दिया गया था। वर्ष 2017 में अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान किया गया। नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पदोन्नति हमेशा वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर होती है और उपयुक्तता का निर्धारण APARS के आधार पर किया जाता है, लेकिन राजस्थान राज्य द्वारा 4.6.2008 को एक प्रशासनिक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें विशेष रूप से पैरा 12.3 में प्रावधान किया गया था कि आपराधिक मामले या विभागीय जांच के लंबित होने और/या निलंबन के मामले में, ऐसे कर्मचारी की पदोन्नति का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। (अनुलग्नक-7) भारत सरकार द्वारा भी आईएएस और आईपीएस सेवा अधिकारियों से संबंधित इसी प्रकार का परिपत्र जारी किया गया था और 2000 में जारी परिपत्र के समान ही सादृश्य लिया गया था। (अनुलग्नक-8) भारत सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र पर राजस्थान राज्य द्वारा संबंधित अधिकारियों के पक्ष में विचार किया गया है, जो पहले से ही उनके खिलाफ जारी आपराधिक मामले या अभियोजन प्रतिबंधों का सामना कर रहे थे, लेकिन सामंजस्यपूर्ण निर्णय दिया गया। वर्ष 2000 में जारी परिपत्र की व्याख्या के अनुसार, राजस्थान राज्य द्वारा ऐसे आईएएस/आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, भले ही वे पदोन्नति के समय आपराधिक मामले का सामना कर रहे हों। (अनुलग्नक-9) प्रतिवादी राजस्थान राज्य ने आईएएस/आईपीएस अधिकारियों और राज्य अधिकारियों के संबंध में दो अलग-अलग व्याख्याएं अपनाई हैं, जबकि दोनों परिपत्रों की भाषा लगभग एक जैसी है। जहां तक आईएएस/आईपीएस अधिकारियों का सवाल है, राजस्थान राज्य ने परिपत्र की

व्याख्या उनके पक्ष में की है कि यदि आरोप तय नहीं किए गए हैं, तब तक अधिकारी पदोन्नति पाने के हकदार हैं, उन्हें पदोन्नति दी जा सकती है, लेकिन राज्य अधिकारियों के मामले में केवल एफआईआर के आधार पर, पदोन्नति का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा, भले ही पदोन्नति के समय राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय न किए गए हों। अपीलार्थी पदोन्नति आरएएस संवर्ग में 2012-13 की रिक्ति के विरुद्ध होनी थी और 1.4.2012 तक अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए थे और आरोप वर्ष 2017 में तय किए गए थे और ये मामले राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के मुख्य पीठ के समक्ष विचाराधीन हैं। वर्ष 2000 में आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के संबंध में जारी परिपत्र और राज्य सेवा अधिकारियों के संबंध में 4.6.2008 को जारी परिपत्र के अवलोकन के अनुसार, लगभग समान हैं, लेकिन राजस्थान राज्य ने आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के पक्ष में परिपत्र की व्याख्या की, लेकिन राज्य कर्मचारियों के लिए परिपत्र की व्याख्या नकारात्मक तरीके से की गई। अपीलार्थी ने माननीय मुख्यमंत्री, जो कार्मिक विभाग के मंत्री भी हैं, को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और 5.10.2020 को प्रमुख सचिव, डीओपी को एक प्रतिलिपि भेजी गई और ऊपर उल्लिखित समान प्रार्थना की गई, लेकिन प्रतिवादियों ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकारक की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 1.11.2012 के आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी की 2012-13 की रिक्ति के विरुद्ध आरएएस सुपर टाइम स्केल के पद पर पदोन्नति के लिए परिणाम खोलें तथा परिणाम खोलने के पश्चात अपीलार्थी को 2012-13 की रिक्ति के विरुद्ध आरएएस, सुपर टाइम स्केल के पद पर सभी परिणामी लाभों सहित पदोन्नति की अनुमति दी जावे। साथ ही अपीलार्थी के मामले पर विचार करें तथा उसे आरएएस, उच्च सुपरटाइम स्केल के पद पर उस तारीख से पदोन्नति दें, जिस तारीख को उसके कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था, जो वर्ष 2017 से संबंधित है तथा सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नति आदेश जारी किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्याय संगत नहीं है। चूंकि अपीलार्थी के विरुद्ध अपराधिक मामला लंबित था, जिसके कारण

अपीलार्थी का पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है। अपीलार्थी को सुनने का पूरा अवसर प्रदान किया गया है। तत्पश्चात् अभियोजन स्वीकृति जारी की गई और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल किया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध अपराधिक मामला होने के कारण पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त किया गया, परंतु उसमें कोई ठोस आधार नहीं था। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब-उल-जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपराधिक मामला अपीलार्थी के विरुद्ध लंबित होने के कारण उसे पदोन्नति से नहीं रोका जा सकता। चूंकि शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा के.वी. जानकी रमन वाले मामले के संबंध में भारत सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 14.09.1992 जारी किया गया, जिसमें यदि कोई संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अपराधिक मामला चल रहा है तो उसे एडहॉक पदोन्नति प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी दिनांक 26.11.1993 को परिपत्र जारी किया गया और उक्त परिपत्र के.वी. जानकी रमन वाले निर्णय के आधार पर जारी किया गया और इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 04.06.2008 जारी किया गया, जिसमें कोई सख्त, कठोरता नहीं दिखाई गई और पदोन्नति आदेश उनके संबंध में जारी किये गये, जो अपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं। एक मामला हनुमानाराम जिसका एसीबी में ट्रायल चल रहा था, उसे पदोन्नत किया गया। इसी प्रकार अधिकरण द्वारा कई आदेश जारी किये गये, जिसकी पालना में राज्य सरकार ने बंद लिफाफे को खोला, जो अपराधिक मामले का सामना कर रहे थे। परंतु वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के पदोन्नति के संबंध में बंद लिफाफे में रखे गये परिणाम को उनके द्वारा लिफाफा नहीं खोला गया, जो नियम विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आरएएस में सीधी भर्ती द्वारा आरपीएससी के माध्यम से दिनांक 24.02.1989 को हुई थी। अपीलार्थी को वर्ष 1995 में आरएएस, वरिष्ठ स्केल के पद पर पदोन्नत किया गया था और आगे उसे वर्ष 2007 में आरएएस चयन

स्केल के संवर्ग में पदोन्नति प्रदान की गई थी। दिनांक 1.4.2011 को आरएएस चयन स्केल के संवर्ग में वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें चयन वर्ष 2005-06 के पदोन्नत व्यक्ति के रूप में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 95 पर रखा गया था। (अनुलग्नक-4) इसी प्रकार आरएएस सीनियर स्केल संवर्ग में दिनांक 1.4.2012 को अगली वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 87 पर दर्शाया गया था। (अनुलग्नक-5) उसे वर्ष 2012-13 के लिए आरएएस सुपर टाइम स्केल के संवर्ग में उसकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिलनी थी तथा अपीलार्थी के मामले पर विचार किया गया था, लेकिन अपीलार्थी के परिणाम को दिनांक 1.11.2012 के आदेश द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। (अनुलग्नक-1) जिसमें पात्र अभ्यर्थियों को आरएएस सुपरटाइम स्केल के पद पर डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नति दी गई, परंतु अपीलार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसकी पदोन्नति परिणाम को बंद लिफाफे में रखा गया। अपीलार्थी के विरुद्ध एफआईआर संख्या 202/2007 धारा 420, 467, 468, 471, 167, 120(बी), 13(1)(डी) एवं 13(2) आईपीसी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज की गई। माननीय न्यायालय में कोई चार्ज फ्रेम अपीलार्थी के विरुद्ध किये गये। आदेश दिनांक 10.12.2012 के द्वारा अपीलार्थी को बहाल कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा जाना नियमों एवं विधि के अनुसार सही नहीं है। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के आरएएस सुपरटाइम स्केल के पद पर पदोन्नति के संबंध में रखे गये बंद लिफाफे को नहीं खोले जाने का प्रश्न है, उक्त मामले के संबंध में मुख्य विचारणीय बिंदु निम्न प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी के विरुद्ध एसीबी प्रकरण लंबित होने के आधार पर बंद लिफाफे को नहीं खोले जाने का प्रश्न है -

अपीलार्थी के विरुद्ध एफआईआर संख्या 167/2011 धारा 7, 13, (1) (डी) रेड विद 13(2) एवं 120बी आईपीसी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज की गई, जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम नं. 2, जयपुर में अपीलार्थी के विरुद्ध चार्ज फ्रेम कर आपराधिक मामला संख्या 81/2016 (59/2011) राजस्थान राज्य बनाम अनिल पालीवाल एवं अन्य दिनांक 16.05.2017 को दर्ज किया गया,

जिसमें अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जो आज तक लंबित है। आज दिनांक तक अपीलार्थी के विरुद्ध रिक्ति वर्ष 2013-14 के विरुद्ध डीपीसी आयोजित तिथि 20.10.2014 तक कोई चार्ज (आरोप) फ्रेम नहीं किये गये हैं। डीपीसी आयोजित तिथि तक न तो कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी और न ही माननीय न्यायालय में कोई चार्ज फ्रेम अपीलार्थी के विरुद्ध किये गये।

राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 12.7 में उल्लेख किया गया है – “*विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजसेवक की पदोन्नति हेतु चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में इसलिये रखी जाती है कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित है अथवा वह निलम्बित है। चयन की यह सिफारिश जो बन्द लिफाफे में रखी जाती है वह इस शर्त के साथ होती है कि राजसेवक के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण में वह दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए तो पदोन्नत किया जाए। इस प्रकार की स्थिति में जब यदि राजसेवक उसके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक/फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए, तो सम्बन्धित प्राधिकारी बन्द लिफाफा खोलकर राजसेवक को पदोन्नत करने की कार्यवाही नियमानुसार करे। इसके लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समक्ष प्रकरण पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है।”*

उक्तानुसार स्पष्ट है कि यदि राजसेवक के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण में वह दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए तो पदोन्नत किया जाए। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक के द्वारा निलम्बन से बहाल किया जा चुका है और वर्तमान समय में राज्य सरकार में अपनी सेवायें दे रहा है, परंतु विभाग द्वारा बन्द लिफाफे को नहीं खोला जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

2. तथ्यात्मक आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध माननीय एसीबी न्यायालय न्यायालय के समक्ष मामला ट्रायल पर होने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग

द्वारा बंद लिफाफे को नहीं खोलने एवं उसे पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है –

ऐसे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जानकी रमन एवं अन्य (1991) 4 एससीसी 109 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :-

"(1) It is only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued. To deny promotion the disciplinary/criminal proceedings must be at the relevant time pending at the stage when charge-memo/charge-sheet has already been issued to the employee.

(16.) On the first question, viz as to when for the purposes of the sealed cover procedure the disciplinary/criminal proceedings can be said to have commenced, the Full Bench of the Tribunal has held that it is only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued. The pendency of preliminary investigation prior to that stage will not be sufficient to enable the authorities to adopt the sealed cover procedure. We are in agreement with the Tribunal on this point. The contention advanced by the learned counsel for the appellant-authorities that when there are serious allegations and it takes time to collect necessary evidence to prepare and issue charge-memo/charge-sheet, it would not be in the interest of the purity of administration to reward the employee with a promotion, increment etc. does not impress us. The acceptance of this contention would result in injustice to the employees in many cases. As has been the experience so far, the preliminary investigations take an inordinately long time and particularly when they are initiated at the instance of the interested persons, they are kept pending deliberately. Many times they never result in the issue of any charge-memo/charge-sheet. If the allegations are serious and the

authorities are keen in investigating them, ordinarily it should not take much time to collect the relevant evidence and finalise the charges. What is further, if the charges are that serious, the authorities have the power to suspend the employee under the relevant rules, and the suspension by itself permits a resort to the sealed cover procedure. The authorities thus are not without a remedy."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी S.B.Civil Writ Petition No. 18074/2018 Sandeep Kumar Barar V/s State of Rajasthan & Ors. वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 को निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :-

"Similar orders passed by the Department in the case of Shri Dinesh M.N., IPS and Shri A. Ponnuchamy, IPS are also reproduced for ready reference :

"Shri Dinesh M.N., IPS (RJ:1995), Managing Director, RAJSICO is hereby promoted in the Selectdion Grade (Pay Band-4: Rs. 37400-67000; plus Grade Pay Rs. 8700). Grade of the Deputy Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8900) and Grade of the Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 10000) of Indian Police Service with effect from 09.05.2014. The said scales/grades are granted subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

"Shri A. Ponnuchamy, IPS (RJ:1991) is hereby promoted in the Grade of Additional Director General of Police (HAG Rs. 67000-79000) of Indian Police Service with effect from 27.10.2016 i.e. date of reinstatement in service subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

In view of the above mentioned orders, it is clear that it has been a regular practice of the Department to promote the police officials subject to the decision of the criminal proceedings pending against them. Therefore, on the sole ground of discrimination, the present writ petition of the petitioner deserves to be allowed.

For the reasons discussed above, the writ petition succeeds and is hereby allowed. The respondents are directed to open the sealed cover pertaining to the recommendation of the screening meeting qua the petitioner. If the petitioner has been recommended for promotion, he be accorded promotion which shall be subject to the outcome of the criminal proceedings pending against him. The required orders be

passed within a period of one month from the date of receipt of the copy of the present order."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B.Civil Writ Petition No. 17238/2015 Kailash Chand Bohra V/s State of Rajasthan वाले मामले में भी दिनांक 16.05.2017 को आदेश पारित किया, जिसमें भी निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :-

"Undeniably, petitioner's case was considered for promotion by the DPC, but the result has been kept in sealed cover as has been informed by the counsel for the State-respondents. The sealed cover has not been opened only owing to pendency of the criminal proceedings against the petitioner. It is also not denied that identically situated employee namely Shri Hanuman Ram Bishnoi, who is a co-accused along with the petitioner, in the same crime pending trial before the jurisdictional Court, has been accorded promotion. No reasons have been put forth for not according same treatment to the petitioner.

Learned counsel for the State-respondents neither in response to the writ application nor to the additional affidavit, detailed any reason as to why a differential treatment has been accorded in the matter of petitioner. Similarly placed persons, have been accorded benefit of promotion subject to outcome of criminal proceedings against them. There is no reason why the petitioner cannot be allowed similar treatment.

For the reasons and discussion aforesaid, the writ application succeeds and is hereby allowed. Respondents are directed to open the sealed cover and proceeded accordingly.

In case, the petitioner has been recommended for promotion, he would be accorded all consequential benefits on notional basis, subject to outcome of criminal proceedings pending against him."

इसी प्रकार "Shri Dinesh M.N., IPS and Shri A.Ponnuchamy, IPS are also reproduced for ready reference :-

"Shri Dinesh M.N., IPS (RJ:1995), Managing Director, RAJSICO is hereby promoted in the Selection Grade (Pay Band-4: Rs.37400-67000;plus Grade Pay Rs.8700). Grade of the Deputy Inspector General of Police (Pay Band: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.8900) and Grade of the Inspector General of

Police (Pay Band: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.10000) of Indian Police Service with effect from 09.05.2014. The said scales/grades are granted subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

"Shri A. Ponnuchamy, IPS (RJ:1991) is hereby promoted in the Grade of Additional Director General of Police (HAG Rs. 67000-79000) of Indian Police Service with effect from 27.10.2016 i.e. date of reinstatement in service subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

In view of the above mentioned orders, it is clear that it has been a regular practice of the Department to promote the police officials subject to the decision of the criminal proceedings pending against them. Therefore, on the sole ground of discrimination, the present writ petition of the petitioner deserves to be allowed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5880/2019 Mukesh Modepatel versus State of Rajasthan & Others में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 जिसमें उपरोक्त आदेशों के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित किया है :-

"In view of the ratio as laid down in the above mentioned judgment and in view of the above observations, the present writ petition deserves to be and is hereby allowed.

The respondents are directed to open the sealed cover pertaining to the recommendation for the promotion of the present petitioner. If the petitioner has been recommended for promotion, he be granted promotion which shall be subject to the outcome of the criminal proceeding pending against him. The required order be passed within a period of two months from the date of receipt of the present order."

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र-आदेश दिनांक 26.11.1993 जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही/माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के संबंध में कार्मिक की पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं :-

"These instructions have been reviewed carefully in the light of Supreme Court judgement dated 27.8.91 in Union of India etc. V/s K.V.Jankiraman etc. (A.I.R. 1991 SC/2010). As a result of review and in supersession of this department circular order noted above, the

procedure to be followed in this regard by the authorities concerned is laid down in the following paras for their guidance.... :-

SIX MONTHLY REVIEW OF 'SEALED COVER' CASES :-

It is necessary to ensure that the disciplinary case/criminal prosecution instituted against any Government servant is not unduly prolonged and all efforts to finalise expeditiously the proceedings should be taken so that the need for keeping the case of a Government servant in a sealed cover is limited to the barest minimum. It has, therefore, been decided that the appointing authorities concerned should review comprehensively the cases of Government servants, whose suitability for promotion to a higher grade has been kept in a sealed cover on the expiry of 6 months from the date of convening the first Departmental Promotion committee which had adjudged his suitability and kept its findings in the sealed cover. Such a review should be done subsequently also every six months. The review should, inter alia, cover the progress made in the disciplinary proceedings/criminal prosecution and the further measures to be taken to expedite their completion.

PROCEDURE FOR ADHOC PROMOTION :-

In spite of the six monthly review referred in para 4 above, there may be some cases, where the disciplinary case/criminal prosecution against the Government servant is not concluded even after the expiry of two years from the date of the meeting of the first DPC, which kept its findings in respect of the Government servant in a sealed cover. In such a situation the appointing authority may review the case of the Government servant, provided he is not under suspension to consider the desirability of giving him adhoc promotion keeping in view the following aspects....."

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी के मामले में उक्त एसीबी प्रकरण दर्ज होने के उपरांत मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर चार्ज फ्रेम इत्यादि हो चुके हैं और प्रकरण ट्रायल पर चल रहा है और अपीलार्थी को वर्तमान मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबन से बहाल भी किया जा चुका है और इस प्रकार अब हमारे मत में अपीलार्थी के पदोन्नति के संबंध में डीपीसी अभिशंषा को बंद लिफाफे में रखा जाना उचित प्रकट नहीं होता है। उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में बंद लिफाफे को खोला जाना एवं परिणाम घोषित किया जाना

उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 01.11.2012 जिसके द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है, को अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर रिक्ति वर्ष 2012-13 के विरुद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का परिणाम जो बंद लिफाफे में रखा गया है, उसे खोलकर परिणाम घोषित किया जावे और अपीलार्थी को आरएएस सुपरटाईम स्केल में नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे और उस तिथि से जिससे अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पदोन्नति आदि का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी पदोन्नति आदि सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी की उक्त पद पर पदोन्नति माननीय एसीबी न्यायालय में लंबित प्रकरण के निर्णयाधीन रहेगी। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष